हर किसी को अपने ज्ञान पर घंमड है पर किसी को भी अपने घंमड का ज्ञान नहीं है।
– अज्ञात

विचार-प्रवाह देहरादून बुधवार 29 जुलाई 2020

पेज थ्री
www.page3news.in

यूएन के पुनर्गठन का मुद्दा

प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इस मौके का जिक्र करते हुए कहा कि यह सही समय है जब यूएन को ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा उपयोगी बनाने पर विचार किया जाए। इस सचाई से तो कोई मुंह नहीं चुरा सकता कि आज की दुनिया द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की दुनिया से बहुत अलग है।

नवीन सिंह।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय आर्थिक व सामाजिक परिषद की बैठक में यूएन के पुनर्गठन का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। ध्यान रहे, संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना के 75वें साल में है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इस मौके का जिक्र करते हुए कहा कि यह सही समय है जब यूएन को ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा उपयोगी बनाने पर विचार किया जाए। इस सचाई से तो कोई मुंह नहीं चुरा सकता कि आज की दुनिया द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की दुनिया से बहुत अलग है। बीच में बनी दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था भी अतीत की बात हो चुकी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहां दफन हुआ, कोई नहीं जानता। शीतयुद्ध कब का समाप्त हो चुका है, हालांकि गृहयुद्ध दुनिया के कई इलाकों की पहचान बने हुए हैं। परमाणु शक्ति संपन्न पांच देशों के अलावा कई सारे देश न केवल यह शक्ति हासिल कर चुके हैं बल्कि अपनी आर्थिक साख बढ़ाकर विश्व रंगमंच पर अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उसमें आज के दौर का शक्ति संतुलन जाहिर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ सबसे अहम सवाल यह जुड़ा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र की पुनर्रचना के लिए दबाव बना रहे देशों की तरफ से क्या अभी अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठ रही है, जिससे पता चले कि यूएन के बदले हुए स्वरूप के जरिये वे एक अधिक न्यायसंगत दुनिया की बुनियाद रचेंगे?

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के दौर में विश्व व्यवस्था भले दो ध्रुवीय रही हो, पर ऐसे देश और नेता मौजूद थे जो दोनों महाशक्तियों के गलत कदमों की खुलकर निंदा करते थे और इससे होने वाला नुकसान भी खुशी–खुशी कबूल करते थे। गुटनिरपेक्षता की वकालत करने वाले ये नेता मानते थे कि अगर सही का समर्थन और गलत का विरोध करने की वजह से उनका देश थोड़ा पिछड़ता भी है तो आगे चलकर वह पिछड़ापन दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर देश का सामूहिक विवेक सो जाएगा तो उसकी भरपाई लाख विकास करके भी नहीं की जा सकती। ऐसे देश और ऐसे नेता आज कहीं नहीं दिख रहे।

स्वाभाविक है कि ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी मनमानी पर अंकुश लगाने वाली कोई शक्ति, कोई शख्सियत कहीं भी नजर नहीं आती। न देश में न विदेश में। अलबत्ता एक अच्छी बात इधर यह हुई है कि अंतरराष्ट्रीय सामूहिक विवेक को जगाने वाले कई सारे कारक आज दुनिया में मौजूद हैं। सोशल मीडिया ने एक ऐसा ऑडिएंस तैयार कर दिया है जो छोटे से छोटे जन समुदाय के कष्ट की भी अनदेखी नहीं होने देता। जो देश की सीमा से ऊपर उठकर मसलों को देख सकता है और उन पर खुलकर बहस कर सकता है।

सूचनाएं अब भुलावे की गलियों में भटकने को मजबूर नहीं हैं। ऐसे में कुछ देश, कुछ राजनेता अगर एक अधिक मानवीय संयुक्त राष्ट्र बनाने की चर्चा शुरू करें तो आने वाले दिनों में बिना किसी महाशक्ति के रहमोकरम के भी इस बदलाव को आकार दिया जा सकता है।

संतोष की तलाश

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। आज हममें से हरेक खुशी और शांति की तलाश कर रहा है। यह खोज सर्वव्यापी है। आखिरकार दुःखी तो कोई भी नहीं रहना चाहता। लोग अलग–अलग तरीकों से खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ इसे धन–दौलत और दुनियावी चीजों में ढूंढते हैं। कुछ इसे यश और प्रसिद्धी में पाना चाहते हैं। कुछ इसे सांसारिक रिश्तो–नातों में तलाष करते हैं। कुछ लोग फिल्म, संगीत, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, टी.वी. और शारीरिक भोगो–रसों जैसे दुनियावी मनोरंजनों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। अन्य लोग खेलकूद देखकर या उनमें भाग लेकर खुशियों की तलाश करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शराब और अन्य नशीले पदार्थों के जरिए खुशियाँ पाना चाहते हैं। अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के द्वारा ही खुशियाँ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

संपादकीय

जनेऊधारी शिवभक्त

मंदिर के बरक्स राजनीति की कितनी ठोस जमीन मंडल तैयार कर सका, इस पर बहस की पूरी गुंजाइश है, मगर ध्यान देने की बात है कि धर्म और जाति पर आधारित ये दोनों राजनीतियां अंततः भावनाओं की राजनीति ही थीं, जिसका तोड़ रोजी–रोटी और अन्य बुनियादी जरूरतों पर आधारित राजनीति ही हो सकती थी। मगर बीजेपी की अगुआई में चल रहे इस घोर दक्षिणपंथी अभियान की काट के तौर पर वैकल्पिक राजनीति की जमीन तैयार करने का जो काम वाम दलों और अन्य धर्मनिरपेक्ष ताकतों को करना था, वह राष्ट्रीय परिदृश्य से पूरी तरह गायब रहा। गौर करें तो उस पूरे दौर में राजनीति की नई जमीन तैयार करने का काम जाने–अनजाने अगर किसी एक और नेता ने किया तो वह थे वीपी सिंह। बतौर प्रधानमंत्री मंडल कमिशन की सिफारिशें लागू करने का फैसला करके उन्होंने तत्कालीन राजनीति का व्याकरण बदलने का प्रयास किया। उनकी चाल भांपने में आडवाणी ने एक पल भी नहीं लगाया। उन्हें पता था कि वीपी सिंह का मंडल कार्ड चल गया तो हिंदुत्व की राजनीति का भट्ठा बैठ जाएगा। सो वे तत्काल राम रथ यात्रा पर निकल पड़े। बिहार में लालू प्रसाद ने उन्हें गिरफ्तार करके उनकी रथयात्रा रोकी और बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर वीपी सिंह की सरकार गिरा दी। ध्यान रहे, वीपी सरकार राम रथयात्रा के सवाल पर गिरी, मंडल पर नहीं। बीजेपी विरोध की पूरी कवायद विभिन्न दलों और गुटों का गठजोड़ बनाने तक ही सिमटी रही। यही वजह है कि आज सभी दलों को बीजेपी और संघ की बनाई पिच पर ही खेलना पड़ता है और राहुल गांधी को भी बीजेपी से लोहा लेने के लिए खुद को कभी जनेऊधारी ब्राह्मण तो कभी शिवभक्त के रूप में पेश करना पड़ता है।

बल्कि बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि ये लोग मंदिर निर्माण से जुड़े किसी भी पहलू का विरोध करें और वे उन पर टूट पड़ें, उन्हें हिंदू विरोधी, राम विरोधी, मंदिर विरोधी वगैरह साबित करें।

राजनीतिक प्रसाद

प्रणव प्रियदर्शी

अयोध्या के राममंदिर मामले में लंबी अदालती लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। उस फैसले के अनुरूप ही बाकायदा समिति बनाकर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसलिए अभी महामारी के इस माहौल में अचानक इस प्रक्रिया को लेकर इस तरह का हाइप क्रिएट कर देने का कोई कारण नहीं था। आज जब देश में लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लोगों को भरसक घरों में ही रहने को कहा जा रहा है, हर तरह की धार्मिक गतिविधियां जब करीब–करीब ठप हैं, तब अचानक एक मंदिर के शिलान्यास को लेकर इस तरह तूमार बांधा जाने लगे, बताया जाने लगे कि शिलान्यास में कितने किलो की चांदी की ईंट होगी और कैसे मंदिर पहले दोमंजिला होना था लेकिन अब तीन मंजिलों वाला होगा, यह कोई सामान्य बात नहीं है।

साफ है, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यह न केवल मौजूदा माहौल में सरकार को अपने लिए सुविधाजनक लग रहा है बल्कि लंबे समय में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की राजनीति के लिहाज से भी मददगार है। ऐसे में बिल्कुल स्वाभाविक है कि सरकार और सत्तारूढ़ संगठन इस आयोजन को हर संभव तरीके से हाइलाइट करें। असल सवाल तो यह है कि विरोधी

पार्टियां कहां हैं? यह सब न उनके लिए सुविधाजनक है, न उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने वाला है। बेहतर होता कि वे इस तरह के आयोजन में मौजूद विसंगतियों को सामने लातीं। लेकिन उनके नेता मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। यह और बात है कि बीजेपी को उनके विरोध की कोई परवाह नहीं है। बल्कि बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि ये लोग मंदिर निर्माण से जुड़े किसी भी पहलू का विरोध करें और वे उन पर टूट पड़ें, उन्हें हिंदू विरोधी, राम विरोधी, मंदिर विरोधी वगैरह साबित करें। शायद इस वास्तविकता को समझ कर ही विपक्षी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। भारतीय राजनीति का यह दिलचस्प मोड़ है जहां सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार अपनी मनमानी चलाती है और विरोधी पार्टियां यह सोच कर मुंह सिले रहती हैं कि अगर विरोध किया तो सत्तापक्ष को ही फायदा हो जाएगा। आजाद भारत में शायद ही किसी सरकार को ऐसी सुविधाजनक स्थिति मिली हो। सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। यह अपने आप हुआ या किन्हीं सोचे–समझे प्रयासों का नतीजा है?

निश्चित रूप से राजनीति की इस सुविधाजनक स्थिति के पीछे बरसों की मेहनत, सूक्ष्म राजनीतिक दृष्टि और जबर्दस्त कौशल का हाथ रहा है। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद से देखें तो गांधीवादी समाजवाद को अपना ध्येय बताने वाली उदारवादी वाजपेयी लाइन का प्रभाव 1984 के लोकसभा चुनाव में हुई पार्टी की दुर्गति के साथ ही समाप्त हो गया, जब उसे सिर्फ दो सीटें मिली थीं। उसके बाद व्यावहारिक रूप से पार्टी की कमान आडवाणी के हाथ में चली गई। आडवाणी ने अपने पूरे कौशल का इस्तेमाल हिंदुत्व की राजनीति की वह जमीन तैयार करने में किया, जिसका सपना आरएसएस अपनी स्थापना के समय से ही देखता आ रहा था।

उस चुनाव में राजीव गांधी की अगुआई में कांग्रेस ने अपने सांसदों की संख्या भले अभूतपूर्व रूप से बढ़ा ली हो, पर राजनीति की नई जमीन तैयार करना न उसकी प्राथमिकता में था, न ही उसमें इतनी कूवत रह गई थी।

अष्टयोग-5122

	5		1	6		4
	37		37		29	3
2	4		7		6	1
	31	1	28		32	
	6		2		3	7
1	28	4	27		33	
	1		3		4	6

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5121 का हल

6	1	7	4	3	5	2
2	28	4	40	7	35	4
1	2	5	6	4	7	3
5	28	3	38	6	34	1
4	2	6	3	5	1	7
3	31	2	24	1	30	6
7	6	1	4	2	3	5

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

एक नया मील का पत्थर

मोहन। राममंदिर का ताला खुलवाकर हिंदू वोट और शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद में पलटवा कर मुस्लिम वोट साधने की बचकानी कोशिश करती रही। आडवाणी ने ताला खुलवाने पर चुप्पी बनाए रखते हुए शाह बानो मामले को ऐसा पकड़ा कि कांग्रेस की बित्ता भर जीभ बाहर लटकने लगी।

इसके बाद भी आडवाणी का अभियान जारी रहा। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने की कार्रवाई इस अभियान के लिए एक नया मील का पत्थर बनी, जिसने उसी दशक के आखिर तक बीजेपी को गठबंधन के बूते ही सही पर अपना प्रधानमंत्री बनाने का मौका दे दिया। इस अभियान के अगले चरण की अगुआई नरेंद्र मोदी ने की। शुरू में आडवाणी के संरक्षण में और फिर उनके विरोध का सामना करते हुए।